छत्तीसगढ़ की प्रथम विधान सभा
सप्तम सत्र

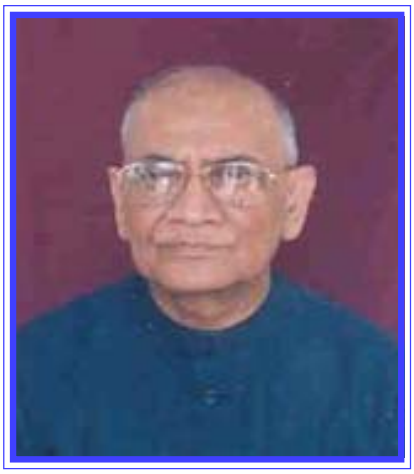

श्री दिनेश नंदन सहाय

राज्यपाल, छत्तीसगढ़

का

अभिभाषण

दिनांक 17 फरवरी, 2003

माननीय सदस्यगण,

नए वर्ष 2003 में विधान सभा के पहले सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनन्दन है । पिछले दो वर्षों में हम सबने मिलकर एक लम्बी दूरी तय की है। मैं आपका ध्यान कुछ उन बातों की ओर दिलाना चाहूंगा जो मैंने इस सदन के पहले अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए 15 दिसम्बर, 2000 को कही थी। मैंने कहा था कि नए राज्य का गठन छत्तीसगढ़ की जनता के लिए उम्मीदों का सूर्योदय तो है ही, साथ ही उनके नुमाइन्दों के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का आप सभी के लिए एक अच्छा अवसर भी है। मैंने कहा था कि मेरी सरकार जनसेवा में एक नई कार्य–संस्कृति का विकास करेगी। मेरी सरकार की सार्वजनिक नीतियां राज्य की जमीनी जरूरतों पर आधारित होंगी। साथ में विकास की अधोसंरचना और सुशासन मेरी सरकार की प्राथमिकताएं होंगी। दो साल मैंने राज्य का लगातार भ्रमण किया है । अनेक लोगों से मिलता रहा हूं। मैंने देखा है कि मेरी सरकार द्वारा किए गए कार्यों से आम जनता का विश्वास और उत्साह लगातार बढ़ रहा है। सबसे अहम् बात यह है कि मैंने प्रदेश के कमजोर वर्गों की आंखों में गौरव और आत्मसम्मान की एक अभूतपूर्व चमक देखी है ।

2. मेरी सरकार, न सिर्फ व्यवस्था की प्रचलित परिपाटियों को सुधारने में सफल रही है, बल्कि दो साल के अल्प–समय में ही अनेक नई मिसालें कायम करने में भी सफल हुई है । सरकार का आकार छोटा रखकर और प्रशासनिक कसावट के कारगर तरीके अपनाकर आज छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों के लिए सुशासन की एक अच्छी मिसाल बन गया है । यही वजह है कि आज जहां देश के अन्य राज्यों का औसतन प्रशासनिक व्यय 80 प्रतिशत से अधिक है, वहीं छत्तीसगढ़ में वार्षिक प्रशासनिक व्यय कुल राजस्व का मात्र 38 फीसदी ही रहा । इस तरह 62 फीसदी हिस्सा आम जनता और विकास के कामों पर खर्च किया गया । बेहतर प्रशासनिक कुशलता से दो सालों में राज्य के राजस्व को, करों की दरों में वृद्धि किए बगैर, 1 हजार 37 करोड़ रू. से 3 हजार 3 करोड़ रू. तक बढ़ाकर विकास और अधोसंरचना में निवेश के नए अवसर बनाए गए हैं । अपने इन अभिनव प्रयासों की वजह से ही मेरी सरकार इतना राजस्व जुटा पाई कि प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त जनता को राहत दिलाने और विकास के काम एक साथ अपने दम पर कर पाई ।

3. छत्तीसगढ़ की 80 फीसदी आबादी की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है । फिर भी खेती करने वाले अन्नदाता किसान गरीबी के कुचक्र से निकल नहीं पाए थे । किसानों की इस स्थिति पर गौर करते हुए मेरी सरकार ने '' राजीव किसान–मितान अभियान '' जैसे अनेक बुनियादी और साहसिक कदम उठाए हैं । कम पैदावार वाले खेतों में, धान की कम लाभदायी किस्मों के बदले बेहतर बिकाऊ किस्में और अधिक दाम देने वाली अन्य फसलें लगाने के अभियान को अच्छी सफलता मिली है । सूखे की छाया के बावजूद बीते दो वर्षों में 5 लाख हेक्टेयर से अधिक रकबे में बेहतर धान, दलहन–तिलहन, उद्यानिकी जैसी अधिक लाभदायक फसलें किसानों ने अपनाई हैं । दोहरी फसलें लेने तथा कृषि–सह–अन्य काम–धंधे

अपनाने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है । किसानों को लाभदायी खेती के लिए प्रशिक्षित करने हेतु एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका अंतिम लक्ष्य गांव–गांव पहुंचकर हरेक किसान को खेती की नई तकनीक सिखाना है ।

4. मेरी सरकार के विशेष प्रयासों से कृषि फसल बीमा का लाभ ज्यादा से ज्यादा किसानों को दिलाने के लिए, आवेदन की मियाद बढ़ाने की कोशिश सफल रही है। इस तरह इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में, राज्य के 5 लाख 35 हजार 162 किसानों को कृषि बीमा से सुरक्षित किया जा सका है। किसानों को अच्छे किस्म का बीज मुहैया कराने के लिए ''छत्तीसगढ़ बीज प्रमाणीकरण संस्था'' की स्थापना की गई है।

5. राज्य में मछली पालन के प्रति किसानों की रूचि बढ़ाने के प्रयासों के अच्छे नतीजे मिले हैं। पहली बार वृहत स्तर पर झींगा पालन तथा अलंकारिक मछली पालन का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। मेरी सरकार के प्रयासों से लगता है कि वह दिन दूर नहीं जब किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया मछली पालन हो जाएगा।

6. बीते दो सालों में सूखे के कारण गांवों में जो हालात पैदा हुए उससे जनता को राहत पहुंचाने के लिए मेरी सरकार ने पहले वर्ष प्रतिदिन औसतन 12 लाख लोगों की रोजी–रोटी का इंतजाम किया । वहीं इस साल फिर सूखे की स्थिति में 15 लाख लोगों को रोजी देने का बीड़ा उठाया है । अभी तक लगभग 12 लाख लोग औसतन प्रतिदिन राहत कार्यों से रोजगार पा रहे हैं । मेरी सरकार की मंशा है कि जब तक और जितनी भी जरूरत होगी, लोगों को राहत पहुंचाई जाए । इसके लिए आवश्यक है कि इस चुनौती का सामना मेरी सरकार और केन्द्र सरकार, दोनों मिलकर करें । मुझे आशा है कि संकट की इन घड़ियों में राज्य सरकार द्वारा राहत कार्यों को चलाने के लिए आवश्यक सहायता केन्द्र सरकार अवश्य उपलब्ध कराएगी ।

7. किसानों को उनकी मेहनत और पसीने की कमाई का उचित दाम मिलने में हो रही दिक्कत को देखते हुए समर्थन मूल्य पर धान खरीदने का फैसला लिया गया । यह भी अन्य राज्यों की तुलना में एक सर्वथा साहसिक निर्णय साबित हुआ है । इस मामले में पुरानी परिपाटियों में ताक पर रखते हुए, अपने दम पर ही, पहले साल लगभग 19 लाख टन और दूसरे साल लगभग 15 लाख टन धान की खरीदी मेरी सरकार ने की । वास्तविक किसानों का धान ही खरीदा जाए और किसानों को बिचौलियों से बचाया जा सके, इसके लिए मेरी सरकार ने धान का उपार्जन इस वर्ष 1 हजार 443 सहकारी समितियों के क्रय केन्द्रों के माध्यम से किया । बिचौलियों की बजाए सीधा लाभ किसानों को देने की मेरी सरकार की नीति से निहित स्वार्थों को तकलीफ अवश्य हुई है, पर सार्वजनिक हित में और प्रदेश के किसानों की भलाई के लिए ऐसा करना जरूरी था । इस तरह किसानों को अपने गांव में, अथवा नजदीक ही, समर्थन मूल्य पर धान बेचने की बेमिसाल सुविधा मिली । इस काम से यह भी साबित हुआ है कि जनकल्याण के लिए मेरी सरकार के फैसले

लाभ–हानि के तराजू पर तौलकर नहीं किए गए, बल्कि सैकड़ों करोड़ रूपये के घाटे की कीमत पर भी किसानों के हित का ख्याल रखना सरकार ने अपना कर्त्तव्य माना ।

8. राज्य में सिंचाई का रकबा 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक करने के लिए विभिन्न स्त्रोतों से, हरसंभव आर्थिक मदद जुटाने की रणनीति बनाई गई । मेरी सरकार ने सिंचाई क्षमता में वृद्धि के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 501 करोड़ रू. का प्रावधान किया है, जो राज्य बनने के समय किए गए प्रावधान के 500 प्रतिशत से अधिक है, और एक कीर्तिमान है । बीते दो सालों में निजी और सरकारी प्रयासों को मिलाकर लगभग 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता हासिल कर ली गई है । शासकीय क्षेत्र में इसका योगदान एक लाख 36 हजार हेक्टेयर है । सिंचाई क्षमता की बढ़ोत्तरी में तेजी लाने के लिए '' टर्न–की पद्धति '' अपनाई गई है । राज्य गठन के बाद 76 नई तथा 74 निर्माणाधीन, इस तरह कुल 391 करोड़ रू. की 150 योजनाओं की प्रशासकीय या पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है ।

9. वृष्टि–छाया क्षेत्रों को प्रकृति का अभिशाप माना जाता है, लेकिन मेरी सरकार ने इन इलाकों की दिक्कतों को बड़ी संवेदनशीलता के साथ महसूस किया और '' इंदिरा खेत–गंगा योजना '' की शुरूआत की। इसी कड़ी में हर संभव तरीके से जल–संसाधन बढ़ाने की दिशा में राहत कार्यों के दौरान बनाई जा रही हजारों '' डबरियां '' मेरी सरकार की सकारात्मक और रचनात्मक सोच की एक और बेहतरीन मिसाल है। इस योजना का लाभ लेकर अब तक लगभग 25 हजार डबरियां प्रदेश भर में स्वीकृत हुई हैं। वृष्टि–छाया क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली शिवनाथ, महानदी, जोंक आदि बारहमासी नदियों तथा नालों पर 75 एनीकट तथा स्टॉपडेम बनाने के लिए स्थल चयन कर लिया गया है। इनमें से 6 एनीकट का निर्माण शुरू कर दिया गया है, ताकि वृष्टि–छाया क्षेत्रों का भूजल–स्तर बढ़ाया जा सके। किसानों के बीच जल–वितरण और अंतिम छोर के खेतों में सही समय तथा सही मात्रा में सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

10. राज्य में लोगों को शुद्ध पेयजल और निस्तार के लिए पर्याप्त पानी मुहैया कराने का बीड़ा मेरी सरकार ने उठाया है। इसके लिए ''इंदिरा गांव–गंगा'' योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कम से कम 40 लीटर प्रति व्यक्ति के मान से पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में 51 हजार 995 बसाहटों में काम पूरा हो चुका है तथा इसी वर्ष के अंत तक 2 हजार 823 बसाहटों में भी यह इंतजाम पूरा हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में 18 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। प्रदेश के सभी 90 विधान सभा क्षेत्रों में कम से कम एक वॉटर–शेड का चयन कर भू–जल संवर्धन कार्यों को गति देने का काम जोर पकड़ रहा है। इस कार्यक्रम में आगामी दो वर्षों में काफी काम कर लिए जाएंगे। भू–जल संवर्धन की महत्ता को देखते हुए ''राज्य स्तरीय भू–जल संवर्धन प्रकोष्ठ'' का गठन किया गया है।

11. पिछले अधिवेशन में मैंने जल–स्वास्थ्य के लिए क्रांतिकारी बदलाव की मुहिम छेड़ने की बात कही थी। आज मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरी सरकार की वह मुहिम अब सफलता के नए–नए आयामों की ओर बढ़ रही है। हर बसाहट में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए ''इंदिरा स्वास्थ्य मितानिन योजना'' लागू की गई। चुनी गई मितानिनों के प्रशिक्षण का दौर चल रहा है। गरीबी किसी भी व्यक्ति की बड़ी से बड़ी बीमारी के इलाज में आड़े नहीं आए इसके लिए अब ''राजीव जीवन रेखा कोष'' से सहज मदद उपलब्ध है। जिला चिकित्सालयों को सर्वसक्षम तथा अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है । उनमें नए–नए उपकरण लगाए जा रहे हैं । देश के अन्य प्रख्यात अस्पतालों के सहयोग से छत्तीसगढ़ में उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए नीति बनाई गई है, जिसके तहत ''अपोलो'' के बाद ''एस्काट्र्स'' जैसा विश्वस्तरीय अस्पताल राज्य में खोला जा चुका है। इस तरह हृदय रोग और अन्य बड़ी बीमारियों के उपचार और ऑपरेशन के लिए छत्तीसगढ़ के मरीजों की राज्य के बाहर जाने की मजबूरी खत्म हो गई है। क्रांतिकारी बदलाव के लिए चिकित्सा शिक्षा के नए अवसर भी जुटाए गए हैं।

12. मेरी सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को देश की ''ऊर्जा धुरी'' बनाने के लिए हर छोटी–बड़ी संभावनाओं का दोहन किया जा रहा है । बीते दो सालों में विभिन्न निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के साथ, 7 हजार मेगावॉट से अधिक क्षमता के बिजलीघर लगाने के करार किए गए, जिनमें से कुछ की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो चुका है । छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा गंगरेल में 10 मेगावॉट क्षमता के जल विद्युत गृह निर्माण का कार्य प्रगति पर है, जिसे इसी साल पूर्ण करने का लक्ष्य है। कोरबा में 500 मेगावॉट क्षमता का ताप बिजलीघर लगाने की तैयारी की जा रही है। मिनी–माइक्रो जल विद्युत संयंत्रों की 12 परियोजनाएं निजी निवेश के लिए स्वीकृत की जा रही हैं। इसके अलावा धान की भूसी पर आधारित 53 मेगावॉट क्षमता के बिजली उत्पादन के संयंत्रों की अनुमति दी जा चुकी है ।

13. राज्य बनने के बाद केवल दो वर्षों में बिजली की अच्छी अधोसंरचना विकसित करने के लिए अति उच्चदाब के 11 उपकेन्द्रों सहित कुल 2 हजार 939 उपकेन्द्र स्थापित किए गए। 10 अति उच्चदाब केन्द्रों सहित 1 हजार 939 उपकेन्द्रों और ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई गई। विभिन्न क्षमताओं की विद्युत लाइनों के निर्माण से सभी वर्गों के उपभोक्ताओं को निर्बाध तथा बेरोक–टोक अच्छी गुणवत्ता की बिजली आपूर्ति के इंतजाम तो किए गए हैं, साथ ही किसानों को सिंचाई पम्पों के लिए बिजली कनेक्शन देने को ऊंची प्राथमिकता दी गई। दो वर्षों की इस अल्प अवधि में कुल 36 हजार 350 पम्पों को विद्युत कनेक्शन दिए गए। 168 नए गांवों और 1 हजार 828 मजरे–टोलों में बिजली पहुंचाई गई । इस प्रकार ऊर्जा के क्षेत्र में, मेरी सरकार की यह उपलब्धि न केवल छत्तीसगढ़ के लिए, वरन पूरे देश में एक अभूतपूर्व कीर्तिमान है। ग्रामीण क्षेत्रों में 10 हजार 221 एकल बत्ती कनेक्शन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले गरीब लोगों को प्रदाय किए गए। आगामी 3 वर्षों में वन क्षेत्र के 1 हजार 253 ग्रामों का विद्युतीकरण किए जाने का लक्ष्य है। बंद फेरो एलॉयज उद्योगों के साथ बीमार तथा बंद उद्योगों को नया जीवन देने के उपायों से हजारों लोगों को रोजगार भी मिला है। इस तरह छत्तीसगढ़ में बिजली की शक्ति आम आदमी शक्ति बनी है।

14. छत्तीसगढ़ की राजधानी विश्वस्तरीय, सर्वसुविधायुक्त तथा अत्याधुनिक नगर के रूप में बसे, इसके लिए मेरी सरकार ने बहुत ही पारदर्शी ढंग से स्थल चयन किया। नई राजधानी के जिस हिस्से में कैपिटल काम्पलेक्स का निर्माण होना है, उन तीन गांवों में भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। मेरी सरकार का प्रयास है कि नई राजधानी के लिए अधिक से अधिक शासकीय भूमि का उपयोग हो और कम से कम निजी भूमि ली जाए। फिर भी प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए जो ''पैकेज'' घोषित किया गया है, वह उनका बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में मददगार होगा।

15. नगरीय सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के लिए 2 नगर पालिकाओं को नगर निगम का दर्जा दिया गया है, 9 नगर पंचायतों को नगर पालिका का दर्जा दिया गया तथा एक नई नगरपालिका का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त दो नगर पालिकाओं को नगर निगम का दर्जा देने, एक ग्राम पंचायत को नगरपालिका का दर्जा देने तथा 33 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा देने हेतु प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई है। नगरीय सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के लिए शुरू की गई योजनाएं अच्छी प्रगति कर रही है। ''इंदिरा सरोवर योजना'' के तहत 64, ''नेहरू बाल उद्यान योजना'' के तहत 46, ''राजीव खेल मैदान योजना'' के तहत् 39 और ''इंदिरा विद्या भवन योजना'' के तहत 73 परियोजनाएं हाथ में ली गई हैं। शहरों में सुविधायुक्त बस स्टैण्ड बनाने के लिए ''प्रियदर्शिनी बस स्टैण्ड योजना'' शुरू की गई है। शहरी यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए सड़कों के सुधार की एक बड़ी योजना भी हाथ में ली गई है, और अब इनके परिणाम दिखने लगे हैं।

16. शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों को साफ–सुथरे पक्के आवास मुहैया कराने के लिए ''राजीव शहरी निर्धन आवास योजना'' के तहत दो हजार मकानों का निर्माण शुरू किया गया है। ''वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना'' में भी झुग्गीवासियों के लिए 18 सौ आवास बनाए जा रहे हैं। सफाई कामगारों के आवास के लिए ''पं. सुन्दरलाल शर्मा सफाई कामगार योजना'' शुरू की गई है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए ''मिनीमाता शहरी निर्धन बीमा योजना'' प्रारंभ की गई है जिसका लाभ 38 हजार 236 लोगों को मिल चुका है।

17. छत्तीसगढ़ में पंचायत राज संस्थाओं को मेरी सरकार ने एक नई पहचान के साथ तराशा है। ये संस्थाएं अब गांव–गांव में पूरी आजादी के साथ गांवों की बेहतरी की योजनाएं बना रही हैं और उन्हें अमल में ला रही हैं। मेरी सरकार संविधान के उन प्रावधानों के प्रति पूरी तरह कटिबद्ध है जिनमें पंचायत राज संस्थाओं के कर्मियों पर स्वशासन की इन इकाइयों के पूर्ण नियंत्रण की भावना निहित हैं। इन कर्मियों की सेवाओं में गुणात्मक सुधार लाने की संभावनाओं पर मेरी सरकार स्थानीय निकायों को उचित मदद और मार्गदर्शन देगी। अपनी बढ़ी हुई जिम्मेदारियों और जवाबदारियों के लिए पंचायत पदाधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामुदायिक स्थानीय संस्थाओं के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकारी–कर्मचारी बाकायदा प्रशिक्षित हों, इसके लिए राजीव गांधी राज्य विकास संस्थान की स्थापना की गई है।

18. पहुंचविहीन बसाहटों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए शुरू की गई ''प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना'' के अमल में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में हैं। इस योजना के तहत 368 सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है तथा 59 सड़कों पर 390 किलोमीटर का डामरीकरण भी किया जा चुका है। सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कारगर व्यवस्था की गई है, वहीं इस कार्य की निगरानी के लिए पंचायत पदाधिकारियों को जागरूक किया गया है। बाद में सड़कों की मरम्मत की जवाबदारी भी पंचायतों को सौंपने का इंतजाम किया गया है।

19. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत गांवों में रोजगार मुहैया कराने के काम में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने प्राप्त आबंटन का सर्वाधिक उपयोग किया है। इस काम में पंचायतों की भूमिका प्रशंसनीय रही। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अमल में भी छत्तीसगढ़ ने अच्छा काम किया है। 39 हजार 377 स्व–सहायता समूह तथा 11 हजार अन्य लोग इस योजना के तहत रोजगार पाने में सफल हुए हैं। ''इंदिरा आवास योजना'' के बेहतर क्रियान्वयन से राज्य में 13 हजार 523 लोगों को लाभ मिला है।

20. अन्य राज्यों की तुलना में प्रशासन के बेहतर और कारगर प्रबंध के कारण छत्तीसगढ़ को बाह्य वित्तीय सहायता, राज्य की अपनी प्राथमिकताओं और शर्तों के आधार पर लेने में कोई कठिनाई नहीं है। गरीबी उन्मूलन की 617 करोड़ रू. का एक बड़ा कार्यक्रम मेरी सरकार, विश्व बैंक की सहायता से छत्तीसगढ़ में शुरू कर रही है। इसी प्रकार सड़क विकास के लिए एशियन डेव्हलपमेंट बैंक (एडीबी) ने एक हजार करोड़ रू. की सहायता स्वीकृत कर दी है तथा परियोजना की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है।

21. ग्रामीण क्षेत्रों में बौद्धिक चेतना के केन्द्रों के रूप में उभरे राजीव ज्ञानोदय केन्द्रों की देख–रेख पंचायतों के जिम्मे की गई है। फिलहाल यह योजना पंचायत मुख्यालय स्तर तक पहुंच चुकी है। मेरी सरकार इन केन्द्रों को ग्राम स्तरीय मल्टी–मीडिया केन्द्र के रूप में विकसित करने जा रही है, ताकि सूचना क्रांति के इस दौर में छत्तीसगढ़ के गांव और युवा पीढ़ी पीछे न रहे। इन केन्द्रों से गांव वालों को उनकी जरूरत की तमाम सूचनाएं, ज्ञान, विचार–विमर्श तथा आगे बढ़ने के अवसरों की जानकारी भी मिलेगी । भविष्य में गांव–गांव में भी राजीव ज्ञानोदय केन्द्र बनाए जाएंगे।

22. मेहनतकश लोगों की जिन्दगी में आने वाली परेशानियों के समाधान के लिए औद्योगिक न्यायालय की स्थापना कर दी गई है, जिससे श्रम न्यायालयों का कार्य सुचारू ढंग से हो सकेगा और श्रमिकों के मामले तेजी से निपटाए जा सकेंगे। रायपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र में 50 बिस्तर वाला अस्पताल खोले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बाल–श्रमिक प्रथा के निर्मूलन की दिशा में ठोस काम के लिए ''बाल–श्रमिक प्रकोष्ठ'' की स्थापना की गई है। बंधुआ मजदूरों के पुनर्स्थापन के लिए राज्य के सभी जिलों में सर्वे कार्य कराए जा रहे हैं।

23. भूमिहीन श्रमिकों और कृषि श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किए गए विशेष प्रयासों से बिलासपुर जिले के 5 हजार 500 तथा रायपुर जिले के 5 हजार कृषि श्रमिकों को बीमा योजना से जोड़ा गया है । अब आगामी दो वर्षों में इन दोनों जिलों के 20–20 हजार श्रमिकों को बीमा का सुरक्षा–कवच प्रदान करने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है।

24. विधान सभा के पहले अधिवेशन में मैंने कहा था कि मेरी सरकार रोजगारमूलक शिक्षा को प्राथमिकता देगी। बीते दो साल में ही दर्जनों उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थाएं खुलना इस बात की तसदीक करती हैं। एक नवीन पांचवर्षीय चिकित्सा महाविद्यालय, 6 तीन वर्षीय चिकित्सा महाविद्यालय, 21 नए कृषि महाविद्यालय, 6 कृषि विद्यालय, 17 आईटीआई खोले जा चुके हैं। राज्य में 14 स्थानों पर एक वर्षीय पैरा–मेडिकल पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए गए हैं। अगले शैक्षणिक सत्र से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय खोलने की तैयारी है। निजी विश्वविद्यलय अधिनियम के सन्दर्भ में कृषि से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी तक हर तरह के ज्ञान का विकास करने वाले 9 नए विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र की पूंजी और विशेषज्ञता लेकर आ रहे हैं। सरकारी और निजी भागीदारी के अनूठे प्रयोगों से राज्य में शिक्षा के साथ रोजगार के अवसरों में बढ़ोत्तरी होगी।

25. मेरी सरकार ने उच्च शिक्षा के नए आयामों को स्पर्श करने के साथ प्राथमिक शिक्षा को बजबूत बनाने का काम भी बखूबी किया है। पहले साल ''पढ़बो पढ़ाबो–स्कूल जाबे'' और दूसरे साल ''स्कूल जाबो–पढ़के आबो'' अभियानों में पालकों और बच्चों को प्रेरित कर क्रमशः 2 लाख 66 हजार 883 और 6 लाख 84 हजार 163 बच्चों को शाला में प्रवेश दिलाया गया। इसके साथ ही व्यापक जनभागीदारी से ऐसा माहौल बनाया गया कि एक बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करें, बीच में पढ़ाई न छोड़ें। मेरी सरकार ने, एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय के देशव्यापी निर्देश जारी होने के पहले ही राज्य में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम चालू कर अपनी दूरदर्शिता प्रदर्शित कर दी थी। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत राज्य की 21 हजार 472 शालाओं के 26 लाख 96 हजार बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं।

26. दो वर्षों में ही 430 पूर्व माध्यमिक शालाओं, 346 माध्यमिक और 175 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का उन्नयन किया गया। ऊंची कक्षाओं में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम लागू करने का अच्छा असर हुआ है। मेरी सरकार का मानना है कि सूचना क्रांति के इस दौर में कदम से कदम मिलाकर चलने वाला राज्य ही भावी संभावनाओं का आदर्श राज्य बन सकता है। इसलिए राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी की निःशुल्क शिक्षा का बहुत बड़ा कार्यक्रम ''इंदिरा सूचना शक्ति'' के रूप में हाथ में लिया गया है। जाति, वर्ग के बंधनों से मुक्त इस कार्यक्रम से अब राज्य की 1 हजार 314 सरकारी शालाओं के एक लाख 30 हजार विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है। आम जनता को उसकी आसान पहुंच में शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अब ''इंदिरा सूचना शक्ति'' केन्द्रों को ''आभासीय'' (विर्चुअल) तहसील और शासकीय दफ्तर बनाने की दिशा में भी मेरी सरकार बढ़ रही है।

27. हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को यदि अवसर मिले तो वे बड़ी से बड़ी प्रतियोगिताओं में जाकर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हाल ही में हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी 5 पदक जीतकर लौटे, जिसमें से 3 स्वर्ण पदक हैं। मेरी सरकार मानती है कि हमारी खेल प्रतिभाएं भी राज्य में उपलब्ध अनगढ़ हीरे के समान हैं, जिन्हें तराशने के यत्न मात्र से उनकी चमक निखर उठती है। छत्तीसगढ़ की माटी में खेलने वाले युवाओं को शिखर पर पहुंचाने का रास्ता बनाने का बीड़ा भी मेरी सरकार ने उठाया है। इसके लिए जशपुर, पेण्ड्रा, कोंडागांव, कोरिया, कोटा और बिलासपुर में स्टेडियम का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है। धमतरी, कवर्धा, जगदलपुर, जांजगीर–चांपा और रायगढ़ में खेल मैदानों का निर्माण किया जा रहा है। एशिया के सबसे बड़े शारीरिक शिक्षा संस्थान की पहली शाखा अभनपुर के ग्राम भरेंगाभाटा में खोलने के लिए 250 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। जशपुर में हॉकी की परम्परा को आगे बढ़ाने के लिए एस्ट्रोटर्फयुक्त हॉकी मैदान बनाया जा रहा है और सरगुजा विकास पैकेज के अन्तर्गत जशपुर में कन्या क्रीड़ा परिसर भी बनाया जा रहा है। राजनांदगांव में राज्य का पहला खेल छात्रावास शुरू कर दिया गया है। राज्य की प्रतिष्ठा को नया आयाम देने के लिए अन्तरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाने का फैसला मेरी सरकार ने किया है। इसके लिए नए राजधानी परिसर में 90 एकड़ जमीन दी गई है। करीब 60 करोड़ रू. की लागत से इस स्टेडियम का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाने वाला है। खिलाड़ियों को सम्मान के साथ ही आर्थिक सुविधाएं और सम्मान–निधि देने की व्यवस्था भी की गई है।

28. मेरी सरकार ने सिर्फ दो साल के अल्प समय में कई प्रभावकारी योजनाएं बनाकर उन पर अमल किया है। ''इंदिरा हरेली सहेली योजना'', अनुसूचित जाति–जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा भूमिहीन परिवारों को आमदनी का जरिया देने के साथ पर्यावरण के सुधार में उनकी भागीदारी तय करने वाली योजना है । इस योजना से 92 हजार लोगों को लाभ मिल रहा है। आबादी भूमि के निःशुल्क पट्टे देने के अभियान से 6 लाख 4 हजार 764 लोगों को उन जमीनों के पट्टे मिले हैं, जिन पर वे काबिज तो थे, लेकिन उन्हें कोई अधिकार नहीं मिला था। इन पट्टों से उन्हें भूमि–स्वामी का हक मिल गया है, जिसका उपयोग वे बैंकों से मकान बनाने या अन्य किसी काम के लिए ऋण लेने में कर सकते हैं।

29. विगत अधिवेशन में मैंने कहा था कि अच्छी सड़कों के बिना विकास की मंजिल तय नहीं की जा सकती। इसीलिए, वर्ष 2002–2003 को सड़क वर्ष के रूप में मनाने का फैसला मेरी सरकार ने किया था। आज मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ की पहचान अब शानदार सड़कों के लिए भी होने लगी है। अभी तक 5 हजार 800 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण, नवीनीकरण, डामरीकरण और मजबूतीकरण किया जा चुका है। उत्तर–दक्षिण कॉरीडोर एवं पूर्व–पश्चिम कॉरीडोर की सड़कों का कार्य शुरू हो गया है। इन सड़कों की लंबाई 2 हजार 960 किलोमीटर है। अच्छी सड़कों के लिए अब तक 1 हजार 86 करोड़ रू. का आवंटन देकर मेरी सरकार ने संकल्पों को साकार करने की दृढ़ इच्छा–शक्ति की मिसाल भी पेश की है।

30. लोकहित के बड़े कामों के लिए, बड़ी सोच का वातावरण बनाना और बड़े कदम उठाना, मेरी सरकार की कार्य प्रणाली की विशेषता बनकर उभरी है। यह बड़ी सोच, कमजोर और सबसे कमजोर तबकों की भलाई का तंत्र विकसित करने का भी जरिया बनी है। मेरी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है कि छत्तीसगढ़ की तरक्की और खुशहाली केवल कुछ इलाकों तक ही सीमित न रहे। क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाने के लिए हाल ही में सुदूर दक्षिण इलाकों के लिए विशेष ''बस्तर पैकेज'' और उत्तर के दुर्गम क्षेत्रों के लिए ''सरगुजा पैकेज'' का निर्णय लिया गया। इसके लिए बस्तर और सरगुजा में मंत्रिमंडल की बैठकें आयोजित कर, वहां के विकास के फैसले वहीं लेना कारगर कदम साबित हुआ है। बस्तर के सम्पूर्ण विकास के लिए 11 सूत्रीय पैकेज तथा सरगुजा के विकास के लिए 20 सूत्रीय पैकेज घोषित कर उसे पूरा करने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के चहुंमुखी विकास के लिए कुल बजट का आधा हिस्सा खर्च करने की प्रणाली बना ली गई है। इन तबकों के बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते हुए आश्रम शालाओं और छात्रावासों की संख्या बढ़ाई गई है। जनभागीदारी के तहत 175 विद्यालयों का उन्नयन किया गया। बस्तर और सरगुजा पैकेज के अंतर्गत 58 नए छात्रावास खोले जा रहे हैं तथा 610 प्राथमिक–माध्यमिक शालाओं को आश्रम शालाओं में बदला जा रहा है। कमार और पहाड़ी कोरवा जनजाति के लिए क्रमशः धमतरी और अंबिकापुर में एक–एक शिक्षा परिसर स्थापित किया जा रहा है। पिछड़े वर्गों के छात्र–छात्राओं के लिए भी 4 पोस्ट–मैट्रिक छात्रावास खोले जा रहे हैं। इस तरह नवीन आश्रम एवं छात्रावास शुरू होने से 22 हजार से अधिक छात्र–छात्राओं को अतिरिक्त आवासीय सुविधाएं मिलेंगी जो अल्प अवधि में किए गए कामों का एक कीर्तिमान होगा। प्रतिभावान छात्रों को अखिल भारतीय परीक्षाओं के लिए अच्छा प्रशिक्षण देने के लिए ''छत्तीसगढ़ राज्य स्टडी सर्किल'' का गठन किया गया है। अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान विद्यार्थियों को उत्कृष्ट आवासीय शालाओं में प्रवेश दिलाने के लिए ''जवाहर आदिम जाति उत्कर्ष योजना'' शुरू की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों को आर्थिक विकास के लिए वित्तीय सुविधाएं सुलभ कराने ''छत्तीसगढ़ राज्य अन्त्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम'' गठित किया गया है ।

31. अपनी परम्परा और संस्कार की तरह जंगलों को बचाते आए स्थानीय वनवासियों को ही जंगलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए जनोन्मुखी वन नीति बनाकर संयुक्त वन प्रबंधन पर जोर दिया गया। 6 हजार 687 संयुक्त वन प्रबंधन समितियां बनाई जा चुकी हैं। जंगलों की सुरक्षा में भी इन समितियों की अहम भूमिका तय की गई है। वन संरक्षण में जन सहयोग के बतौर वन सुरक्षा समितियों का हिस्सा 10 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ को वनौषधि राज्य बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए समस्त 32 वन मंडलों में लोक संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। राज्य में औषध वनस्पति मंडल गठित किया गया है, जिसके तहत 9 परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ किया गया है। इस तरह वनौषधियों के संरक्षण तथा संवर्धन का ठोस कार्य शुरू कर दिया गया है। 21 वन मंडलों में वन विकास अभिकरण का गठन किया गया है। इन अभिकरणों से कराई जाने वाली 12 परियोजनाओं की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई है। वनोपज संग्रह के काम में लगे मजदूरों को वास्तव में मालिक बनाने की दिशा में मेरी सरकार

ने ठोस कदम उठाए हैं। उसके कारण तेंदूपत्ता संग्रहण के व्यापार से शुद्ध लाभ से बोनस के रूप में 79 करोड़ 10 लाख रू. संग्राहकों को दिए जा चुके हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से 16 करोड़, 18 लाख रू. का ऋण लेकर 7 लाख बोरे की भंडारण क्षमता वाले 47 गोदामों का निर्माण भी किया जा रहा है। यह तेंदूपत्ते को सुरक्षित रखकर, बाजार में सही दाम दिलाने की दिशा में उठाया गया सही कदम है। सिंचाई, खनिज और ऊर्जा से संबंधित 30 परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त की गई है, जिससे वन अंचल में विकास कार्यों में तेजी आएगी। वन क्षेत्र से लगे 5 किलोमीटर परिधि में आने वाले ग्रामों के समन्वित विकास का दायित्व प्रायोगिक तौर पर राज्य के कुछ हिस्सों में वन विभाग को सौंपा गया है।

32. राज्य की विलक्षण जैव–विविधता को संरक्षित करने के लिए मेरी सरकार सजग है। अब राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान तथा 11 वन्य प्राणी अभ्यारण्य स्थापित हो चुके हैं। सीतानदी, उदन्ती के साथ ही अचानकमार अभ्यारण्य को भी ''प्रोजेक्ट टाइगर'' के रूप में मंजूरी मिल गई है। इस तरह राज्य में प्रोजेक्ट टाइगर प्रक्षेत्रों की संख्या भी एक से बढ़कर 3 हो जाएगी। बिलासपुर के ''कानन पेण्डारी'' को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा ''चिड़ियाघर'' के रूप में मान्यता दी गई है । साथ ही, ''नन्दनवन'' को भी लघु चिड़ियाघर का आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। रायपुर और बिलासपुर में दो राजीव स्मृति–वनों का विकास किया गया है, जिनमें लगातार काम जारी है।

33. प्रचुर मात्रा में उपलब्ध खनिज संसाधनों से स्थानीय आबादी को लाभान्वित करने पर मेरी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। इसलिए खनिजों के खनन और खनिज धारित क्षेत्रों के विकास का काम सरकार काफी सावधानी से कर रही है। राज्य में खनिज विकास निगम की स्थापना से खनिज के कारोबार को सुचारू बनाने में मदद मिली है।

34. रेत की रायल्टी समाप्त करने का ताजा फैसला यह जाहिर करता है कि मेरी सरकार प्राकृतिक संसाधनों को आम लोगों के अधिक से अधिक उपयोग के लिए यथासंभव मुफ्त में उपलब्ध कराने में भी कोई संकोच नहीं करती। इसी भावना से बंसोड़ों और पान की खेती करने वाले किसानों को रायल्टी–मुक्त बांस देने तथा वनोपज के कारोबार में स्थानीय लोगों को अधिक मजदूरी और लाभांश देने के निर्णय लिए गए हैं।

35. औद्योगीकरण और अधोसंरचना विकास में निवेश का वातावरण बनाने में छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जिसने प्रशासन की जिम्मेदारियों को अधिनियमित किया है। ''अच्छी अधोसंरचना'' और ''अच्छा प्रशासन'' के स्थायी उपायों से आकर्षित होकर राज्य में 60 हजार करोड़ रू. के पूंजी निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है और छत्तीसगढ़ के प्रति पूंजी निवेशकों का विश्वास भी निरंतर बढ़ रहा है। इनमें से बहुत से उद्योग स्थापित भी होने लगे हैं। नए परिदृश्य में इस्पात, एल्यूमीनियम तथा विद्युत उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़, देश का अग्रणी प्रदेश बनने की राह पर चल पड़ा है। अपने खनिजों और प्राकृति विशेषताओं की बदौलत ही इस दिशा में राज्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। विकास की दौड़ में क्षेत्रीय संतुलन और स्थानीय

अनुकूलताओं के आधार पर विशिष्ट औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिए की गई पहल के अच्छे परिणाम आने लगे हैं। भिलाई में सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क स्थापित किया गया है। टेडेसरा और बोरई में फूड पार्क की स्थापना का काम शुरू हो चुका है। इसी प्रकार बस्तर में एग्रो पार्क, कोरबा में एल्यूमीनियम पार्क, रायपुर में एपारेल पार्क तथा सिलतरा में सायकल कॉम्पलेक्स की स्थापना का काम गति पकड़ चुका है। हर जिले में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए कदम उठाए गए हैं और इस हेतु उद्योग विभाग को 900 एकड़ भूमि का आधिपत्य प्राप्त हो चुका है।

36. सहकारिता आंदोलन में स्वच्छ परम्पराओं को प्रोत्साहित करने के लिए मेरी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। किसानों की सीधी भागीदारी तय कर सहकारिता को कृषि आधारित औद्योगिक क्रांति से जोड़ा गया है। मुझे खुशी है कि इस सोच के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ का पहला भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना शीघ्र उत्पादन प्रारंभ कर देगा। इसी कड़ी में बालोद और चम्पारण में भी सहकारी शक्कर कारखाने स्थापित करने की तैयारी हो चुकी है।

37. मेरी सरकार ने छत्तीसगढ़ के परम्परागत हस्त–शिल्प और हाथकरघा के विकास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का बीड़ा भी उठाया है। हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ का गठन किया गया है। हस्त–शिल्प को बड़े बाजारों में सम्मान दिलाने के लिए भी ठोस पहल की गई है। शासकीय विभागों और उपक्रमों में लगने वाले वस्त्रों का प्रदाय हाथकरघा क्षेत्र से करने के फैसले के कारण राज्य के 45 हजार बुनकरों के परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। हाथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण, टेक्नालॉजी उन्नयन, डिजाइन विकास, क्वालिटी कन्ट्रोल आदि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में ''शबरी'' एम्पोरियम खोलने सहित विभिन्न महानगरों में प्रदर्शनियां आयोजित करने जैसे उपायों से छत्तीसगढ़ के हस्त–शिल्प राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बना चुके हैं।

38. छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा धार्मिक महत्व के स्थलों से बाहरी दुनिया को अवगत कराने के लिए मेरी सरकार ने पर्यटन बढ़ाने के विशेष प्रयास किए हैं। छत्तीसगढ़ में पर्यटन के लिए जरूरी अधोसंरचना की विकास योजनाएं हाथ में ली गई हैं। विशिष्ट महत्व के स्थानों के विशेष प्रचार–प्रसार के जरिए पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है। सरकार के इन प्रयासों को केन्द्र शासन ने भी सराहा है और ''राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2002–03'' से नवाजा है। नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, मिस्र तथा लंदन में आयोजित राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय पर्यटन समारोहों में छत्तीसगढ़ ने पुरस्कार और सराहना अर्जित की है। सरगुजा पैकेज के अन्तर्गत पाट विकास अभिकरण की स्थापना जैसे निर्णयों से नये गैर–पारम्परिक पर्यटन गंतव्यों का विकास हो सकेगा।

39. अपनी धरोहर और अपनी माटी का गौरव बढ़ाने वाले लोगों से नई पीढ़ी को परिचित कराने को मेरी सरकार ने अपना कर्त्तव्य माना है यही वजह है कि राज्य की पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने और छत्तीसगढ़ के यशस्वी साहित्यकारों, कला साधकों एवं महापुरूषों की स्मृतियों को जीवित रखने का निरन्तर प्रयास किया गया है पुरासंपदा को संरक्षित करने हेतु विभिन्न पुरातात्विक महत्व के स्थलों जैसे भोरमदेव मंदिर (कवर्धा), शिव मंदिर (गनियारी), देवरानी–जेठानी मंदिर (ताला) आदि के रासायनिक संरक्षण का काम कराया गया है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जिला पुरातत्व संघ के गठन का कार्य लगभग पूर्णता पर है। रायपुर में बुद्ध जयंती पर प्रदर्शनी, राजनांदगांव में लोक मड़ई उत्सव, बिलासपुर में बिलासा महोत्सव, भिलाई में पदुमलाल पुन्नालाल समारोह एवं सरगुजा में रामगढ़ उत्सव जैसे आयोजन कर सांस्कृतिक गतिविधियों को विकसित और सुदृढ़ करने के सार्थक प्रयास किए गए हैं। जरूरतमंद साहित्यकारों और कलाकारों को मासिक सम्मान राशि (पेंशन) दी जा रही है।

40. मेरी सरकार द्वारा मुक्तांगन संग्रहालय बनाने का कार्य प्रांरभ कर दिया गया है। राज्य के समस्त सूत्रों एवं राज्य में फैली विविध सांस्कृतिक संस्थाओं को एक नया आयाम देने के लिए बहुआयामी संस्कृति संस्थान की स्थापना की महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की जा रही है। 11 वें वित्त आयोग के अंतर्गत पुरातत्व संरक्षण योजना एवं ग्रंथालय विकास योजना प्रारंभ की गयी है। इसके अंतर्गत राज्य में फैली पुरासंपदा को सहेजने का प्रयास किया जा रहा है तथा राजधानी स्थित ग्रंथालय के उन्नयन का कार्य किया जा रहा है।

41. मेरी सरकार ने महिलाओं के सम्मान को उनकी आत्मनिर्भरता से जोड़कर सकारात्मक पहल की है। राज्य में 33 हजार से अधिक महिला स्व–सहायता समूह गठित हो गए हैं, जिनमें 4 लाख से अधिक महिलाओं को संगठित किया गया है। इन समूहों के गठन को सुनियोजित और व्यवस्थित रूप देने के लिए ''इंदिरा महिला स्व–सहायता समूह मिशन'' शुरू किया गया है। अनेक स्तरों पर महिलाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देने की योजनाएं अमल में लाई जा रही हैं। एकीकृत महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम, ''पुनरीक्षित इंदिरा महिला योजना'' को 17 विकासखंडों में लागू किया गया है। 3 जिलों में स्व–शक्ति परियोजना चलाई जा रही है। प्रदेश में 20 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों से 20 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु ''उदिशा प्रशिक्षण परियोजना'' के अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित कराए गए हैं। नाबार्ड से ऋण लेकर एक हजार आंगनबाड़ी भवन बनाना भी प्रस्तावित है। मेरी सरकार ने आयुष्मति योजना में एक नया आयाम जोड़ते हुए भूमिहीन एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को जिला चिकित्सालय में मिलने वाली सुविधा को अब विकासखंड चिकित्सालयों में भी देने का निर्णय लिया है। सरगुजा जिले में कम वजन वाली गर्भवती और शिशुवती माताओं और किशोरी बालिकाओं को निःशुल्क अनाज देने के लिए ''मिनी माता पोषण आहार योजना'' शुरू की गई है। इस योजना के तहत 24 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

42. निराश्रित महिलाओं को सहारा देने के लिए शुरू की गई ''इंदिरा सहारा योजना'' से एक लाख से अधिक महिलाओं का आत्मविश्वास पुनः जागा है और अब वे स्व–सहायता समूहों से जुड़कर या अन्य योजनाओं से स्व–रोजगार अपनाने लगी हैं। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए ''राज्य महिला आयोग'' के साथ ही दहेज उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए प्रदेश के 9 नए जिलों में ''दहेज प्रतिषेध सलाहकार बोर्ड'' का गठन किया गया है। राज्य के निःशक्त, निराश्रित तथा वृद्धजनों के कल्याण और पुनर्वास के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन व्यापक जनभागीदारी और करगर ढंग से किया जा रहा है।

43. पिछड़ेपन को तेज विकास में बदलने के लिए ''सूचना प्रौद्योगिकी'' का उपयोग मेरी सरकार ने बड़ी सावधानी से किया है। यह माना गया है कि सूचना क्रांति के दौर में दुनिया के कंधे से कंधा मिलाकर ही छत्तीसगढ़ को विकास की मुख्यधारा में लाया जा सकता है। नए जमाने में रोजगार के नए अवसरों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा की अनिवार्यता को राज्य गठन के समय ही पहचान लिया गया और छत्तीसगढ़ में उसके लिए उचित अधोसंरचना और वातावरण के विकास का काम हाथ में लिया गया। ''इंदिरा सूचना शक्ति'' के बाद ''सब्बो बर कम्प्यूटर योजना'' भी कम्प्यूटर साक्षरता के लिए देश में अपनी तरह की पहली योजना है।

44. आम जनता की सहूलियतों से जुड़े हुए विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ ऑन लाइन इन्फर्मेशन फॉर सिटीजन इम्पॉवरमेंट (चॉइस) परियोजना के तहत विशिष्ट योजनाएं बनाई गई हैं। जन–शिकायत निवारण प्रणाली को वीडियो कॉन्फरेन्सिग से जोड़कर लोगों का दुख–दर्द बांटने और उनकी समस्याएं सुलझाने में मेरी सरकार की पहल भी देश में अग्रणी मानी गई है। ''भुइयां'' ग्रामीणों की तकलीफें दूर करने की दिशा में अपनी तरह का अनोखा कार्यक्रम हैं। इसके तहत नक्शा, खसरा और बी–वन की कम्प्यूटरीकृत नकल गांव वालों को देने की व्यवस्था की गई है। प्रारंभिक चरण में 16 तहसीलों में यह इंतजाम किया गया है। राज्य की सभी तहसीलों में यह सुविधा उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है। आम जनता से जुड़ी प्रशासनिक सेवाओं जैसे –राजस्व संग्रहण, जांच चौकियों की व्यवस्था को भी कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। इस तरह मेरी सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से खाई विहीन समाज की रचना का संकल्प पूरा करने की दिशा में मजबूत शुरूआत की है। ''गांव डाहर चलव'' अभियान के तहत ग्रामीण जनता ने अपने गांव की जनरपट बनाई है। गांव वालों द्वारा बनाई गई जनरपट को ग्राम सभाओं के बाद जिला पंचायतों ने भी अंगीकार कर लिया है और जिलों की जनरपट भी बन चुकी है। जनरपट की प्रक्रिया में लगभग 20 हजार संगवारी और दो लाख स्वैच्छिक कार्यकर्त्ता युवा जुड़े रहे। अब छत्तीसढ़ की जनरपट बनाने का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। इस तरह मानव विकास के प्राथमिक समंक जुटाने के साथ ही ग्रामीणों की मर्जी के विकास का प्रारूप बनाने का काम करने वाला देश में छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा।

45. मेरी सरकार ने आर्थिक सुधारों की दिशा में जनोन्मुखी कदम उठाए हैं। पूर्व प्रचलित व्यवस्था में से ऐसे क्षेत्रों को सरकार ने अपने सीधे नियंत्रण से मुक्त किया है, जहां निजी क्षेत्र से अधिक कार्यकुशलता

की संभावना हो। सड़क परिवहन, आवास जैसे क्षेत्रों में गैर–जरूरी शासकीय उपस्थिति हटाई गई है, वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में निजी भागीदारी बढ़ाई गई है। इस तरह किफायती औरा गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने की दिशा में सरकार ने कारगर कदम उठाए हैं।

46. मेरी सरकार ने अपना प्रशासनिक व्यय नियंत्रित अवश्य रखा है, परन्तु अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए शासकीय और स्थानीय निकायों में रोजगार के अवसर कम नहीं किए हैं। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए पूर्व निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 35 वर्ष कर दिया गया है। विशेष भर्ती अभियान चलाकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र की जा रही है।

47. मेहनती और शांतिप्रिय लोगों ने छत्तीसगढ़ को एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। यह पहचान सामाजिक समरसता और बेहतर कानून–व्यवस्था को भी रेखांकित करती है। छत्तीसगढ़ में कानून और व्यवस्था का राज कायम करने में पुलिस की भूमिका अच्छे नागरिकों के लिए दोस्ताना और जरूरतमंदों के लिए संवेदनशील तथा अनुशासित है। राज्य में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में भी पुलिस की भूमिका उल्लेखनीय रही है। पुलिस की सक्रियता से राज्य में अनुसूचित जनजाति के विरूद्ध अपराधों में 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के विरूद्ध अपराधों में 20 प्रतिशत कमी आई। राज्य में सीमित पुलिस बल का युक्तियुक्त उपयोग करते हुए भी मेरी सरकार ने सरगुजा में पुलिस महानिरीक्षक रेंज तथा तीन नए पुलिस जिले बीजापुर, बलरामपुर और नारायणपुर में गठित किए गए हैं। उग्रवाद समस्या प्रभावित क्षेत्रों के लिए तीन नई बटालियन गठित की गई है। उप जेल राजनांदगांव, जशपुर, कोरबा तथा बैकुण्ठपुर को जिला जेल का दर्जा दिया गया और कवर्धा तथा बीजापुर में उप जेल का निर्माण किया जा रहा है।

48. कोई गरीब कानूनी सहायता से वंचित न रहे, इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह व्यवस्था न्याय प्रणाली को भी मजबूती प्रदान करेगी। न्यायिक सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए ''राज्य न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान'' बिलासपुर में शीघ्र खोलने की तैयारी है। बिलासपुर में उच्च न्यायालय का नवीन भवन और परिसर बनाने को भी मेरी सरकार प्राथमिकता देगी। राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त व्यवहार न्यायाधीश के पदों की पूर्ति की जाएगी।

49. लोक आयोग, मानव अधिकार आयोग और छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग जैसी स्वतंत्र उच्चाधिकार प्राप्त संस्थाओं का गठन भी किया जा चुका है। सार्वजनिक जीवन में शुचिता बनी रहे, इसकी महती जिम्मेदारी जनता के नुमाइन्दों पर भी है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन स्थापित वैधानिक प्रक्रियाओं का सहारा लेकर गंभीरता के साथ किए जाने वाले हर प्रयास को संरक्षण देने वाली संस्थाओं को, मेरी सरकार पूरा सहयोग दे रही है।

50. मैंने देखा है कि माननीय सदस्य सदन में जिस दरवाजे से प्रवेश करते हैं उसके ऊपर लिखा है – ''संसदीय प्रजातंत्र का पुरूषार्थ या सफलता इस बात पर है कि विधान मंडल जनता की कठिनाइयों और दुख–दर्द का हल निकाल सके।'' मुझे यह वाक्य बहुत ही पसंद है। साथ ही खुशी है कि आप सभी ने इसी मंत्र के आधार पर दो वर्षों में जनता की कठिनाइयों और दुख–दर्द का हल निकालने के कारगर कदम उठाए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम विधानसभा में जनता के नुमाइन्दों की भूमिका में आप सभी का इतिहास में एक गौरवमय स्थान है। इस विधानसभा के शेष कार्यकाल में भी आम लोगों की खुशहाली और सामाजिक न्याय के आपके प्रयासों को सफलता की नई ऊंचाइयां प्राप्त हों, ऐसी मेरी शुभकामना है।

धन्यवाद ! जय हिन्द !,